नौवीं योजना के दौरान पंजाब में स्थापित किए जाने हेतु प्रस्तावित चीनी मिलें

3713. **श्री इकबाल सिंह** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क)नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार द्वारा पंजाब में कितनी चीनी मिलें स्थापित किए जाने की संभावना है;

(ख) पंजाब में चीनी मिलों को स्थापित करने के लिए इस समय लम्बित पड़े आवेदनों का ब्योरा क्या है; और

(ग)सरकार द्वारा इस संबंध में कौन-कौन से प्रभावी तथा आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्री तथा खाद्य मंत्री और नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) केन्द्र सरकार देश के किसी भी भाग में चीनी मिलें स्थापित नहीं करती । तथापि, यह नई चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करती है ।

(ख) 31 मार्च, 1997 को पंजाब में चीनी मिल स्थापित करने के लिए दो आवेदन थे:

क्र.सं.	आवेदक का नाम	प्रस्तावित स्थान
1.	मैसर्स एग्रो बोर्ड इंडस्ट्रीज लि.	कुरकाली, फतेहपुर, जि. रोपड़।
2.	सुनील गुप्ता	लुधियाना जिले के किसी भी अनुमतियोग्य क्षेत्र में.

(ग) क्र. स. 1 के आवेदन पर लाइसेंसिग समिति द्वारा पहले ही विचार कर लिया गया है जबकि हाल ही में प्राप्त अन्य आवेदन पर विचार किया जाना अभी बाकी है ।

Import of Wheat and Comparison of Imported and Domestic Wheat in terms of quality and price

3714. SHRI SUNDER SINGH BHANDARI:
SHRI 1SH DUTT YADAV:
SHRI RAM GOPAL YADAV:

Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) the total amount of wheat to be imported in 1997 and, how much of it has reached India;

(b) by what time the total quantity will reach the country;

(c) the quality of imported wheat in comparison to Indian wheat as well as the relative price of the two;

(d) the total wheat procured in the country this year; and

(e) the wheat reserves as on 1st May, 1997?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND MINISTER OF FOOD AND MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI CHATURANAN MISHRA): (a) and (b) Government had decided to toliport upto 20.00 lakh tonnes of wheat during 1996-97 and against this the State Trading Corporation of India Ltd., (STC) contracted for import of 16.75 (± 5%) lakh tonnes. A quantity of 14.71 lakh tonnes of wheat has already arrived at Indian Ports as on 2.5.97. The balance quantity is expected to arrive by the middle of May, 1997. Government have since decided to import an additional quantity of 20.00 lakh tonnes of wheat during 1997-98 and against this, the STC has so far contracted a quantity of 10.00 lakh tonnes for import with shipment schedule from July to December, 1997.

I The quality of imported wheat is to conform to the quality, specifications stipulated in the contract between the STC and exporting country. The

acceptability for consumption is determined as per the provisions of PFA Act and phytosanitary aspects. In case of indigenous wheat, the quality at the time of procurement under Price Support Scheme is assessed as per the provisions of uniform specifications prescribed for the particular marketing season. As such the relative price of imported wheat and indigenous wheat cannot be compared.

(d) A total of 35.38 lakh tonnes of wheat has been procured for Central Pool during the current Rabi Marketing Season (1997-98) as on 7.5.1997.

I The stock of wheat in the Central Pool as on 1.4.1997 is estimated at 32.40 lakh tonnes.

किसान संगठनों द्वारा गेहूं के समर्थन मूल्य का विरोध किया जाना

3714. **श्री राम जेठमलानी :** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक किसान संगठनों ने सरकार द्वारा गेहूं के समर्थन मूल्य की घोषणा के प्रति अपना विरोध व्यक्त किया है;

(ख) यदि हां तो किसान संगठनों की मांगें क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने उक्त मांगों पर विचार करने के संबंध में कोई निर्णय लिया है; यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

कृषी मंत्री और खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (ग) भारतीय किसान यूनियन और कुछ अन्य किसान संगठनों ने गेहूं के लिए 550/- रूपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग करते हुए आन्दोलन किया था । खाद्य मंत्री ने 26.4.1997 को चण्डीगढ़ में पंजाब और हरियाणा के मुख्य मंत्रियों के साथ मुलाकात की । इस चर्चा के दौरान सरकार द्वारा गेहूं के पहले ही घोषित 415/- रूपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 60/- रूपये प्रति क्विंटल बोनस राशि में और किसी प्रकार की वृद्धि को नकार दिया गया था । भारतीय किसान यूनियन और अन्य संगठनों द्वारा 28.4.1997 को अपना आन्दोलन वापस लेने के बारे में सूचना मिली है ।

खाद्यान्न उत्पादन और आवश्यकता तथा उत्पादन में अनुमनित अन्तर

3715. **श्री राम जेठमलानी :** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वर्ष 1996-97 के दौरान खाद्यान्न का उत्पादन अधिकतम होने के कारण खाद्यान्न उपलब्धि की स्थिति आसान होने की संभावना है;

(ख) यदि नहीं तो, इस संबंध में सरकार का आंकलन क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में खाद्यान्न की आवश्यकता को पूरा करने के लिए गेहूं का आयात करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो गेहूं की कितनी मात्रा का आयात किया जाएगा और देश में वर्ष 1996-97 के दौरान खाद्यान्न की आवश्यकता तथा उत्पादन में कितना अंतर होने का अनुमान है?

कृषि मंत्री और खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान देश में खाद्यान्नों का उत्पादन क्रमशः 191.50 मिलियन टन, 185.00 मिलियन टन और 192.12 मिलियन टन (संभावित) हुआ । यद्यपि, खाद्यानों की प्रति व्यक्ति निवल उपलब्धता गिरकर 1996 में 496.7 ग्राम प्रति दिन हो गई जो 1995 में 507.7 ग्राम प्रति दिन थी जबकि गेहूं की प्रति व्यक्ति निवल उपलब्धता थोड़ी सी बढ़कर 1996 में 178.9 ग्राम प्रति दिन हो गई जो 1995 मे 172.0 ग्राम प्रति दिन थी ।

(ग) और (घ) केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों का स्टाक स्थिति, देश में खाद्यान्नों के उत्पादन, वसूली प्रवृति, सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अन्य कल्याण योजनाओं की आवश्यकता, खुले बाजार के मूल्यों आदि जैसे विभिन्न घटकों पर विचार करने के बाद सरकार ने 1996-97 और 1997-98 में देश में गेहूं की उपलब्धता बढ़ाने के लिए 2 मिलियन टन तक गेहूं का आयात करने का निर्णय किया था ताकि मूल्यों पर नियंत्रण रखा जा सके ।

गेहूं का स्टाक और गेहूं की कम खरीद

3716. **प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक अप्रैल, 1994, 1995, 1996 और 1997